ASHOKA
SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक
Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress
E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress
संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 24 ● नई दिल्ली ● 01 से 08 जुलाई 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

मध्य प्रदेश भूमि विवाद - कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव पर लगाए आरोप, कहा- जनता कर रही जवाब का इंतजार

रामंदिर चोरी- 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

अयोध्या। दुनिया भर में रामभक्तों की आस्था को आघात पहुंचाने वाले राममंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपितों की पुलिस को रिमांड नहीं मिली। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हुई और आठों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इन आठों को पुलिस ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जज रजत वर्मा ने 13 जुलाई तक आठों आरोपितों की न्यायिक रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अयोध्या में अधिवक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल में सुनवाई का फैसला किया था। राम मंदिर दान गबन मामले में सोमवार को सभी आठों आरोपियों की एंटी करप्शन कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत (जुडिशल कस्टडी) 14 दिनों के

लिए बढ़ा दी है। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने किसी भी आरोपी की कस्टडी रिमांड की मांग अदालत से नहीं की। ऐसे में आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ नहीं होगी और वे न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों और जांच की प्रगति के आधार पर होगी। यह मामला प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर रमाशंकर यादव टिन्नू सहित आठ लोगों के खिलाफ गुरुवार को आठ नामजद व एक अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ रामजन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

ये हैं चढ़ावा चोरी के आरोपित

अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और सुभाष श्रीवास्तव। एसआईटी ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के चालक रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की सिफारिश की थी। यह घटनाक्रम तब हुआ जब विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) भी राम मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी को लेकर एफआईआर की मांग में शामिल हो गई।

राम मंदिर में तैनात आरएमओ अर्जुन देव हटाए गए, 1600 कैमरों की निगरानी की थी जिम्मेदारी

अयोध्या । राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपियों के घर छापेमारी और पूछताछ के बीच श्रीराम जन्मभूमि में 17 वर्षों से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी (आरएमओ) अर्जुन देव को राम मंदिर से हटा दिया गया है। काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। ऐसे में एसआईटी व पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद करोड़ों रुपये के चढ़ावे की चोरी कैसे होती रही और निगरानी तंत्र कहां नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन देव वर्ष 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे। इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर रुक गए। हाल में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया था। एसआईटी अब यह भी खंगाल रही है कि आखिर उनके तबादले बार-बार किसके स्तर से रुकवाए गए और एक ही जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही।

निर्माणाधीन रिसॉर्ट में दीवार ढही, तीन मजदूरों की मौत; लंच टाइम ने टाली बड़ी अनहोनी

जयपुर । जयपुर के चंदवाजी थाना क्षेत्र स्थित तालामोड़ में निर्माणाधीन द अरावली पैलेस रिसॉर्ट में सोमवार को हुए भीषण हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में रिंकू, सविता और रामजी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों का निम्स अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर के भोजन के समय हुआ। उस वक्त कई मजदूर खाना खाने के लिए साइट से बाहर गए हुए थे। प्रशासन का मानना है कि यदि हादसा कार्य के व्यस्त समय में होता तो जनहानि का आंकड़ा और अधिक हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे के नीचे कोई अन्य व्यक्ति फंसा न हो। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

रिफॉर्म्स पर दिल्ली में मंथन- पीएम मोदी ने क्यों बुलाई सभी सचिवों की बैठक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है। सरकार का पूरा जोर देश में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को सुगम बनाने पर है।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई सचिव अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधारों की प्रगति और जन-केंद्रित कदमों का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। क्या भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित देश बन पाएगा? पीएम मोदी पहले ही साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब नेक्स्ट-जेन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की समीक्षा की

जाएगी। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि सभी सचिव शासन और डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी कामों में, विशेषकर आम जनता से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई या पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।

आर्थिक तरक्की और भावी रोडमैप की चुनौतियां

क्या देश की यह तेज आर्थिक रफ्तार आगे भी बरकरार रहेगी? इस उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 7.7 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर और चौथी तिमाही के 7.8 प्रतिशत के आंकड़ों पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है। मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च के दम पर जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। एक साल पहले विकास दर 7 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, पूरे साल की विकास दर भी वित्त वर्ष 2025 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अब 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

बैठक में क्या होगा खास?

विकसित भारत का लक्ष्य- साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए खाका तैयार करना।

रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार- पिछले 10 साल में हुए व्यवस्थागत बदलावों को और आगे बढ़ाना।

जीडीपी में रिकॉर्ड उछाल- वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज हुई 7.7फीसदी की मजबूत आर्थिक विकास दर की समीक्षा।

जीरो पेंडेंसी पर जोर- जनता से जुड़े सरकारी कामों और फाइलों को बिना देरी निपटाने का सख्त निर्देश।

युवाओं के लिए अवसर- देश में रोजगार और युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने पर विशेष फोकस।

प्रशासनिक दिग्गजों की मौजूदगी

इस पूरी कवायद को जमीन पर कौन उतारेगा? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मंत्रियों और अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य जनता के जीवन को आरामदायक बनाना होना चाहिए।

आईआरटीएस आशिमा सिंह राजमाता राजभवन बस्ती और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ऐश्वर्यराज सिंह भारत के रक्षा मंत्री से मिले

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेवानिवृत्त आई.आर.टी.एस. अधिकारी श्रीमती आशिमा सिंह ने आज उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। आशिमा सिंह आई टी आर एस अधिकारी के साथ बस्ती राज परिवार की राजमाता भी हैं। इस अवसर पर राजमाता के साथ राजा बस्ती ऐश्वर्यराज सिंह राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल भी भारत के रक्षा मंत्री से उनके निवास पर मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बस्ती राज परिवार की बात राजभवन बस्ती मे संरक्षित पुरातात्विक धरोहरो पर हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, राजनितिक प्रयासों की सार्थकता तथा 2027 की विधानसभा की चुनावी चुनौतियों पर भी चर्चा की गयी। राजमाता आशिमा सिंह ने अपनी ऐतिहासिक रचनाओं की पुस्तके इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट किया।

कमीशनखोरी के जाल में फंसा राजधानी का स्वास्थ्य विभाग, रडार पर 100 डॉक्टर; अब ऊपर तक पहुंची जांच

दिल्ली । दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच अब शीर्ष प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, 100 से अधिक डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। इनमें घोटाले के दौरान स्वास्थ्य विभाग में अहम पदों पर तैनात कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा कि घोटाला पूरी तरह से कमीशनखोरी से जुड़ा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों व निजी लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार, एसीबी इस मामले की दो स्तरों पर जांच कर रही है। पहले स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक निर्णयों, खरीद संबंधी मंजूरियों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है, जबकि दूसरे स्तर पर केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस), डॉक्टरों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पूर्व डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल, तत्कालीन हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब जांच और तेज होगी।

अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि खरीद प्रस्तावों की मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही। सूत्रों का कहना है कि घोटाले के दौरान स्वास्थ्य विभाग में तैनात कम से कम पांच से सात आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसियों का फोकस केवल टेंडर प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) को भेजी गई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामग्री की मांग का सीपीए की ओर से की गई वास्तविक खरीद से बारीकी से मिलान किया जा रहा है। एजेंसियां संबंधित अस्पतालों के मांग पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड और खरीद फाइलों का भी मिलान कर रही हैं। जांच में कई महत्वपूर्ण खरीद से जुड़े दस्तावेज और मूल फाइलें गायब मिली हैं। गिरफ्तार पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल, पूर्व हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा से पूछताछ में इन्हीं पहलुओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जांच एजेंसी गायब रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, भुगतान संबंधी दस्तावेज की कड़ियां तलाश रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने स्तर पर पसंद के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कर खरीद व्यवस्था पर प्रभाव किया है। सीपीए और उससे जुड़े अहम पदों पर की गई इन तैनातियों का फायदा उठाकर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। यह पूरा मामला कमीशनखोरी के तहत चलाया गया है। 650 करोड़ रुपये के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले में जांच का शिकंजा अब शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच गया है।

ईंधन आपूर्ति और युद्ध की बदलती रणनीति

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार नए आयाम ले रहा है। शुरुआती दौर में जहां संघर्ष मुख्य रूप से जमीनी और हवाई सैन्य अभियानों तक सीमित था, वहीं अब दोनों देश एक-दूसरे की रणनीतिक अवसंरचना को निशाना बना रहे हैं। विशेष रूप से यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। इन हमलों का असर अब रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। स्वयं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया है कि देश के कई हिस्सों में ईंधन की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्षेत्र क्रास्नोदार में स्थित स्लाव्यान्स्क-ना-कुबानी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। रूस के क्षेत्रीय प्रशासन के अनुसार, वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन उनके मलबे से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिफाइनरी से उठता घना काला धुआं दिखाई दिया, जिसने इस हमले की गंभीरता को दुनिया के सामने ला दिया। स्लाव्यान्स्क रिफाइनरी रूस की प्रमुख तेल प्रसंस्करण इकाइयों में से एक है। इसकी वार्षिक क्षमता लगभग 40 लाख टन कच्चे तेल को संसाधित करने की है। यहां से फ्यूल ऑयल, नैफ्था और समुद्री ईंधन जैसे उत्पाद तैयार होकर काला सागर के बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में इस रिफाइनरी पर हमला केवल स्थानीय औद्योगिक क्षति नहीं, बल्कि रूस की ऊर्जा आपूर्ति और निर्यात क्षमता पर भी सीधा प्रभाव डालता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि यारोस्लाव क्षेत्र की एक अन्य रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। यह क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यदि यह दावा सही है, तो यह दर्शाता है कि यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली ड्रोन क्षमता लगातार विकसित हो रही है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ड्रोन खतरे के कारण कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी। इन हमलों का सबसे बड़ा प्रभाव रूस की ईंधन आपूर्ति पर पड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में स्वीकार किया कि देश के कई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है, जो पूरे देश में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी माना कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और परिवहन तथा व्यापार से जुड़े लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सरकार अब घरेलू मांग को प्राथमिकता देने के लिए डीजल निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो इसका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि रूस वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। निर्यात में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। वह सीधे मोर्चे पर रूस की सैन्य शक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ उसकी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता को भी कमजोर करना चाहता है। तेल रिफाइनरियों पर हमले से रूस की सेना के लिए ईंधन उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है। इसके अलावा नागरिक परिवहन, उद्योग और कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं, जिससे सरकार पर आंतरिक दबाव बढ़ता है। दूसरी ओर रूस का कहना है कि वह अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहा है तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन लगातार हो रहे हमले यह संकेत देते हैं कि इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक ऊर्जा केंद्र की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान नहीं है। यही कारण है कि युद्ध अब केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के भीतर सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों का असर आम नागरिकों पर भी पड़ता है। ईंधन की कमी से परिवहन महंगा होता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है और महंगाई बढ़ सकती है। यदि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता लगातार कम होती रही, तो रूस की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात नीति और आपूर्ति प्रबंधन दोनों पर एक साथ काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले ही भू-राजनीतिक तनाव, प्रतिबंधों और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं से प्रभावित है। ऐसे में रूस की रिफाइनरियों पर लगातार हमले तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में किसी भी बड़े उतार-चढ़ाव का असर घरेलू अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। अंततः यूक्रेन द्वारा रूस की तेल रिफाइनरियों पर किए जा रहे ड्रोन हमले यह दर्शाते हैं कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब जीत केवल सैनिकों की संख्या या हथियारों की क्षमता से तय नहीं होती, बल्कि ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक ढांचे और आर्थिक स्थिरता भी युद्ध का महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुके हैं।

रूस के सामने चुनौती केवल सैन्य जवाब देने की नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा व्यवस्था और घरेलू अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखने की है। वहीं यूक्रेन इन हमलों के माध्यम से रूस पर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाए हुए है। आने वाले समय में यह ऊर्जा युद्ध रूस-यूक्रेन संघर्ष की दिशा और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

सम्पादकीय

क्षेत्रीय तनाव की नई चुनौती

पाकिस्तान के कराची शहर में सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हुए हमले के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने देश में मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है और देश की आंतरिक सुरक्षा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि कराची की घटना को लेकर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और अब उसे इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित पाकिस्तान रेंजर्स के एक सुरक्षा शिविर पर हुए हमले में कम से कम तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए। पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग के अनुसार हमलावरों ने पहले मुख्य द्वार पर विस्फोट किया और उसके बाद सुरक्षा घेरे को तोड़कर शिविर में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को विफल करने का दावा किया। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इस घटना के पीछे भारत का समर्थन प्राप्त आतंकवादी समूह हैं। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। भारत ने इसी आधार पर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिना प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोप केवल वास्तविक समस्या से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं। दरअसल, पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर आतंकवादी हिंसा का सामना कर रहा है। कराची के अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हाल के दिनों में कई हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने जियारत स्थित एक सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी प्रकार जमात-उल-अहरार जैसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन संगठनों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन इनकी हिंसक गतिविधियों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय विद्रोही संगठनों को भारत का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर भारत लगातार इन आरोपों से इनकार करता आया है और कहता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा विफलताओं का दोष भारत पर मढ़ने की कोशिश करता है। भारत का यह भी आरोप रहा है कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकवादी संगठन खुले तौर पर सक्रिय हैं, जिन्होंने भारत सहित अन्य देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है।

फिर टूटा छात्रों का भरोसा

प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धी प्रकृति उम्मीदवारों पर दबाव बढ़ाती है जिससे कुछ उम्मीदवार अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लीक हुए पत्रों का उपयोग करने जैसी अनैतिक प्रथाओं का सहारा लेते हैं। अपर्याप्त नियामक निगरानी और प्रवर्तन तंत्र इस समस्या को और भी गंभीर बना देते हैं क्योंकि कमजोर दंड प्रभावी रूप से कदाचार को रोकने में विफल रहते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन भी संगठित समूहों को कागजात लीक करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वे लीक हुए कागजातों को प्रतिस्पर्धी बाजार में मूल्यवान वस्तु के रूप में देखते हैं।

जब तक परीक्षा तंत्र को पवित्र नहीं बनाया जाता, तब तक छात्रों के सपने टूटते रहेंगे और जिन्दगियां खत्म होती रहेंगी। क्या छात्रों की आत्महत्याएं शासन व्यवस्था के लिए महज एक मौत का आंकड़ा ही बनी रहेगी।

हमारे तंत्र की नाकामी और परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों की जबरदस्त घुसपैठ के परिणामस्वरूप पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले तो मई का महीना छात्रों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। नीट, सीबीएसई, एसएसई और सीयूईटी-यूजी परीक्षाओं का आयोजन तो हुआ लेकिन इन सभी परीक्षाओं में अलग-अलग कारणों से विवाद देखने को मिला। कहीं पेपर लीक हुआ तो कहीं तकनीकी कारणों से परीक्षा को दोबारा कराने की नौबत आ गई। अब पेपर लीक होने के चलते महाराष्ट्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई। परीक्षा का स्थगित होना एक बार फिर 6 लाख छात्रों को रुला गया। नीट यूजी परीक्षा तो दोबारा हो गई। अभी इस पर विवाद थमा भी नहीं था कि सीबीएसई बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की गलतियों का भांडा फूट गया। जब छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की री-इवैल्यूएशन करवाई तो अनेक के अंक बढ़ गए। रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल किए और टॉपर बन गई। इससे स्पष्ट है कि छात्रों के भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र के टीईटी पेपर लीक होने का पैटर्न नीट परीक्षा की तरह ही रहा। कुछ लोगों के पास ऐसे प्रश्न पत्र थे जिनके सवाल टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र से मिलते-जुलते थे। पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं। 2002 से लेकर 2026 तक 46 प्रमुख पेपर लीक हुए थे लेकिन परीक्षा निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन मुट्ठीभर अधिकारियों को हटाया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें अदालती दोषसिद्धि भी शामिल है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के मास्टर माइंड विजेन्द्र गुप्ता की तलाश पुलिस कर रही है और अब तक तीन गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार के समस्तीपुर निवासी विजेन्द्र गुप्ता पर पहले भी पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 के एक स्टिंग ऑपरेशन में खुद विजेन्द्र गुप्ता ने बड़े-बड़े दावे किए। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा के औचित्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। अनेक शिक्षाविदों का कहना है कि पहले नीट और टीईटी शिक्षकों को 2028 तक यह परीक्षा पास करने को कहा गया है। नौकरी मिलने के बाद परीक्षाओं को लेकर नीति अर्थहीन है। इसलिए टीईटी की कोई जरूरत ही नहीं है। लाखों छात्रों की सालभर की मेहनत पेपर लीक के चलते बर्बाद हो जाती है तो परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कैसे करें। बार-बार हो रही घटनाओं से छात्रों का शासन व्यवस्था पर भरोसा खत्म हो चुका है। पेपर लीक के चलते छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। नीट परीक्षा लीक होने के बाद देशभर में दर्जनभर छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। कितने ही परिवार जो?ऋण लेकर अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, बुरी तरह से टूट चुके हैं। जब छात्र सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं से लेकर प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं तक, प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने देशभर में अनगिनत छात्रों को प्रभावित किया है। ये उल्लंघन न केवल परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं, बल्कि शैक्षणिक ढांचे के भीतर मौजूद व्यवस्थागत कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के परिणाम केवल व्यवस्थागत बाधाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में जनता के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच समान रूप से चिंताएं बढ़ाते हैं। इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए तकनीकी नवाचारों, कड़े नियामक ढांचे और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रथाओं की नैतिक अनिवार्यता के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने सहित एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। भारत अपनी परीक्षा प्रणालियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है, ऐसे में परीक्षा पत्रों के लीक होने की रोकथाम देशभर में समान अवसर सुनिश्चित करने और शैक्षणिक गतिविधियों की अखंडता को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत में परीक्षा पत्रों का लीक होना एक गंभीर समस्या बन गया है, जिससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता धूमिल हो रही है और हितधारकों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। इन लीक की बार-बार होने वाली घटनाओं के कई कारण हैं। शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी कमजोरियां, विशेष रूप से कमजोर साइबर सुरक्षा उपाय, अपराधियों को डिजिटल प्रणालियों का दुरुपयोग करने और गोपनीय परीक्षा पत्रों तक अवैध रूप से पहुंचने की अनुमति देते हैं। भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख कारण है, जिसमें अधिकारियों और वित्तीय लाभ चाहने वाली बाहरी संस्थाओं के बीच मिलीभगत परीक्षाओं की निष्पक्षता से समझौता करती है। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धी प्रकृति उम्मीदवारों पर दबाव बढ़ाती है जिससे कुछ उम्मीदवार अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लीक हुए पत्रों का उपयोग करने जैसी अनैतिक प्रथाओं का सहारा लेते हैं। अपर्याप्त नियामक निगरानी और प्रवर्तन तंत्र इस समस्या को और भी गंभीर बना देते हैं क्योंकि कमजोर दंड प्रभावी रूप से कदाचार को रोकने में विफल रहते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन भी संगठित समूहों को कागजात लीक करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वे लीक हुए कागजातों को प्रतिस्पर्धी बाजार में मूल्यवान वस्तु के रूप में देखते हैं। जब तक परीक्षा तंत्र को पवित्र नहीं बनाया जाता, तब तक छात्रों के सपने टूटते रहेंगे और जिन्दगियां खत्म होती रहेंगी। क्या छात्रों की आत्महत्याएं शासन व्यवस्था के लिए महज एक मौत का आंकड़ा ही बनी रहेगी। पेपर लीक कांड एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इस लिए सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। शासन व्यवस्था को इस बात का अहसास हो जाना चाहिए कि जब-जब युवाओं के सपनों पर वार होगा तब-तब उनके हाथों में मशाल होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

शिव के पुत्र, पार्वती के गौरव; पोस्टर के साथ जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का एलान; त्रिविक्रम के साथ मिलाया हाथ

जूनियर एनटीआर और निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास एक माइथोलॉजिकल ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें महीनों से चल रही थीं। अब इनकी पुष्टि भी हो गई है। आज सोमवार को पोस्टर रिलीज के साथ फिल्म का आधिकारिक एलान कर दिया गया है। बता दें कि जूनियर एनटीआर के इस प्रोजेक्ट पर महीनों से अटकलें थीं, जो अब खत्म हुईं। फिल्म का एलान कर दिया गया है। मगर, टाइटल सामने नहीं आया है। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर होगा। जूनियर एनटीआर की यह फिल्म भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) पर आधारित बताई जा रही है। कार्तिकेय को हिंदू धर्म में ज्ञान और विजय के देवता माना जाता है। सामने आए पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा है, शिव के पुत्र। पार्वती का गौरव। हमेशा रहने वाले सेनापति। एक बार फिर त्रिविक्रम के साथ। पोस्टर पर त्रिशूल बना हुआ है। किसी किरदार की झलक पोस्टर में साझा नहीं की गई है। पोस्टर में युद्ध से बर्बाद और आग की लपटों से घिरा एक नजारा दिख रहा है, जिसके बीचों-बीच एक विशाल त्रिशूल है। विजुअल डिटेल और कैप्शन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) पर आधारित है। मेकर्स ने अभी तक इस प्रोजेक्ट की कहानी या इससे जुड़ी पौराणिक प्रेरणा के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। बता दें कि जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने साल 2018 में आई फिल्म अरविंदा समेथा वीरा राघव में काम किया था। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत होगा। मेकर्स ने अभी यादा डिटेल्स साझा नहीं की हैं। फिलहाल, पोस्टर देखकर एनटीआर के फैंस उत्साहित हैं।

दुबई के अस्पताल में भर्ती हुईं जैस्मिन भसीन- बर्थडे मनाने बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ गई थीं, गंभीर इन्फेक्शन के कारण बिगड़ी तबीयत

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की दुबई में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ जन्मदिन मनाने दुबई गई थीं।

अली गोनी ने सोशल मीडिया पर अस्पताल से तस्वीरें और वीडियो शेयर कर बताया कि जैस्मिन को एक गंभीर इन्फेक्शन हुआ है और वे अभी डॉक्टरों की देखरेख में रिकवर कर रही हैं। अली ने प्रशंसकों से जैस्मिन के जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की है अली गोनी ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल के कमरे से कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वे अस्पताल के बेड पर आराम कर रही जैस्मिन को गले लगाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जैस्मिन व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। अली ने एक वीडियो भी शेयर किया

है, जिसमें जैस्मिन अस्पताल के कमरे के अंदर ही अपना बर्थडे केक काट रही हैं। इन तस्वीरों के साथ अली ने एक भावुक नोट लिखकर जैस्मिन के बीमार होने की जानकारी दी। अली गोनी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी की कुछ और ही प्लानिंग थी। जन्मदिन की अच्छी यादें बनाने के बजाय हम इस समय अस्पताल के कमरे में हैं। तुम्हें इस तरह दर्द में देखना इस पूरी ट्रिप का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है। अली ने आगे लिखा कि वे जैस्मिन को फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए किसी भी तरह का सेलिब्रेशन छोड़ने को तैयार हैं। लगातार आ रहे फोन और मैसेज के बाद अली गोनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मैसेज और कॉल करने के लिए सभी का शुक्रिया। जैस्मिन अचानक बहुत बीमार हो गईं और गंभीर इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल और भावुक रहे हैं। अली ने माफी मांगते हुए कहा कि वे अभी किसी का फोन नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जैस्मिन की देखभाल पर है। जैस्मिन भसीन और अली गोनी की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। दोनों पहली बार अर्जेंटीना में रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के सेट पर मिले थे। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई। इसके बाद साल 2020 में जब दोनों रियलिटी शो बिग बॉस 14 में शामिल हुए, तब उनका यह रिश्ता प्यार में बदला। इस शो से बाहर आने के बाद दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था और तब से वे लगातार साथ हैं।

काव्या मारन क्या म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध से करेंगी शादी- सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन हैं काव्या

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की शादी की खबरें एक बार फिरचर्चा में हैं। अनिरुद्ध के अंकल और तमिल एक्टर वाई जी महेंद्रन ने दोनों की शादी का दावा किया है। महेंद्रन ने तमिल चैनल केपीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जो बताया गया है, उसके मुताबिक यह शादी पक्की है।

काव्या और अनिरुद्ध की जोड़ी बहुत अच्छी है। हालांकि, अनिरुद्ध और काव्या मारन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। एक्टर वाई जी महेंद्रन ने एक तमिल चैनल केपीटीवी को दिए इंटरव्यू में इस रिश्ते पर बात की। उन्होंने अनिरुद्ध की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। मैं उसे बधाई देना चाहता हूं। वह एक बहुत बड़ी शादी करने जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है, उससे यह बिल्कुल पक्की बात है कि दोनों शादी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने शादी की तारीख या

जगह के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। महेंद्रन ने सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि काव्या कोई साधारण लड़की नहीं हैं। उनमें इतनी बड़ी आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद को संभालने की क्षमता है। उन्हें अपने पिता से बिजनेस के गुण मिले हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और उन्हें साथ आकर म्यूजिकल बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए। अनिरुद्ध और काव्या मारन के अफेयर की चर्चा पहली बार नहीं हुई है। साल 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि दोनों एक साल से यादा समय से रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। उस पोस्ट में यह भी कहा गया था कि अनिरुद्ध के रिश्तेदार और सुपरस्टार रजनीकांत ने इस सिलसिले में काव्या के पिता कलानिधि मारन से मुलाकात भी की थी। साल 2025 में जब शादी की खबरें वायरल हुई थीं, तब अनिरुद्ध रविचंदर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसका खंडन किया था। उन्होंने लिखा था, शादी? मजेदार है। लोग शांत रहें और अफवाहें फैलाना बंद करें। उस समय अनिरुद्ध ने शादी की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया था, लेकिन काव्या मारन को डेट करने के सवाल पर कोई कमेंट नहीं किया था। अब उनके अंकल के बयान के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।

दोनों के बैकग्राउंड की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंदर तमिल सिनेमा के बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं, जिन्होंने साल 2012 में आई फिल्म 3 के गाने व्हाई दिस कोलावेरी डी से अपनी खास पहचान बनाई थी। वे सुपरस्टार रजनीकांत के रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने लियो और कूली जैसी कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया है। दूसरी तरफ, काव्या मारन देश के बड़े मीडिया हाउसेज में से एक सन ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं। काव्या वर्तमान में सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा काम संभालती हैं।

जेनेलिया ने गंगा में लगाई डुबकी, वट पूर्णिमा पर पति रितेश देशमुख को किया याद

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने वट पूर्णिमा के त्योहार पर गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस खास मौके पर उन्होंने अपने पति रितेश देशमुख को याद किया। साथ ही सोशल मीडिया पर इसका एक खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया है। जेनेलिया ने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पर वट पूर्णिमा के त्योहार के दिन गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जेनेलिया ने लिखा, Vat Purnima पर डुबकी लगाई और तुम्हें याद किया- मेरे पति रितेश। जेनेलिया और रितेश बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक हैं। दोनों की मुलाकात साल 2000 के शुरुआत में उनकी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम की शूटिंग के दौरान हुई थी। लगभग 10 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 3 फरवरी 2012 को महाराष्ट्रीयन और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी कर ली। जेनेलिया और रितेश के दो बेटे हैं- रियान और राहिल। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मजेदार और प्यारे पारिवारिक वीडियो शेयर करते रहते हैं। जेनेलिया और रितेश को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म राजा शिवाजी में एक साथ देखा गया था। वट पूर्णिमा शादीशुदा महिलाओं का एक मुख्य हिंदू त्योहार है, जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन बरगद (वट) के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं।

'50 लोगों को दुबई ले गए थे शाहरुख खान', 'हैप्पी न्यू ईयर' के प्रीमियर को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा

हाल ही में फराह खान ने बताया कि शाहरुख ने फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के प्रीमियर के लिए करीब 50 लोगों की पूरी कास्ट और क्रू को अपने खर्च पर दुबई ले गए थे। फराह खान हाल ही में अभिनेता श्रेयस तलपड़े के घर अपने कुकिंग व्लॉग के लिए गई थीं, जहां उनके साथ उनके कुक दिलीप भी थे। बातचीत के दौरान दोनों ने साथ में की गई फिल्मों की यादें ताजा कीं और श्रेयस के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। इसी दौरान फराह ने शाहरुख खान की दरियादिली का जिक्र करते हुए बताया कि वह हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों का खास ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मराठी फिल्मों में भी काफी अलग-अलग और शानदार काम हो रहा है, और उनका बिजनेस भी काफी अच्छा है। फराह ने बताया, 'आजकल मराठी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। पहले रितेश की फिल्म 'राजा शिवाजी' आई और फिर 'देऊल बैंड 2', जिसमें शाहरुख खान ने अपने हिस्से के पैसे छोड़ दिए थे। उन्होंने करीब 42 लाख रुपये छोड़ दिए।' उन्होंने आगे कहा, 'शाहरुख ऐसे ही हैं। जब 'ओम शांति ओम' का प्रीमियर लंदन में हुआ था, तब वह सबको साथ लेकर गए थे। उस समय हम सिर्फ चार लोग थे, लेकिन 'हैप्पी न्यू ईयर' के समय वह करीब 50 लोगों को दुबई लेकर गए थे। इसमें डीओपी, म्यूजिक डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सभी शामिल थे।' फराह ने हंसते हुए यह भी बताया कि इतनी थकान थी कि प्रीमियर के दौरान पूरी स्टार कास्ट ही सो गई थी। फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि जैकी श्रॉफ ने भी अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वहीं, मराठी फिल्म 'देऊल बैंड 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपये से यादा की कमाई की थी। फिल्म के डायरेक्टर प्रवीन तर्दे ने भी इसकी सफलता का कुछ श्रेय शाहरुख खान की दरियादिली को दिया था।

मैं वापस आऊंगा के शॉट्स के बीच दिलजीत दोसांझ चुपचाप करते थे यह काम; अभिनेत्री निक्की नरूला ने किया खुलासा

फिल्म मैं वापस आऊंगा को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभिनेत्री निक्की नरूला ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता पर खुशी जाहिर की है। फिल्म की कामयाबी के बारे में बात करते हुए निक्की ने एक कहा, यह देखकर बहुत खुश हूं कि मैं वापस आऊंगा ने दूसरे हफ्ते में कितनी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। दर्शक फिल्म को जो प्यार दे रहे हैं, उससे साबित होता है कि अच्छी फिल्मों को हमेशा अपने दर्शक मिल ही जाते हैं। यह फिल्म सच में बहुत खूबसूरत है और इतने शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूं। अभिनेत्री ने इस फिल्म को अपने करियर के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक बताया। साथ ही कहा कि सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ काम करना उनके लिए सिर्फ एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे कहीं यादा है। निक्की ने दिलजीत दोसांझ के सरल और मिलनसार व्यवहार की भी तारीफ की। उनके मुताबिक, दुनियाभर में लोकप्रिय होने के बावजूद दिलजीत का विनम्र स्वभाव सबसे खास बात थी। सेट पर बिताए पलों को याद करते हुए निक्की ने बताया कि दिलजीत ने सभी के साथ एक जैसा अपनापन दिखाया, चाहे उनका रोल कुछ भी हो। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पूरी कास्ट और क्रू के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाया। निक्की ने आगे कहा कि उन्हें एक बात खास तौर पर याद है कि दिलजीत शॉट्स के बीच चुपचाप ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अभिनेत्री ने यह भी बताया कि दिलजीत के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान उन्हें घबराहट नहीं हुई। इसके बजाय, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। इस खूबसूरत अनुभव का क्रेडिट उन्होंने सेट के सहज माहौल को दिया। निक्की ने अमर सिंह चमकीला में भी दिलजीत की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की उन्होंने कहा कि वे हर किरदार में ईमानदारी और असलियत लाते हैं।

10वीं के छात्रों के लिए बड़ा फैसला, बोर्ड ने जारी की तीन भाषा नीति की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली । सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड की नई गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों को अब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। आइए समझते हैं नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से। सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के अनुसार मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों पर यह नई त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को आगे चलकर कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे उन्हें जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़ना भी जरूरी होगा।

पॉइंट्स में समझें पूरी गाइडलाइंस

सीबीएसई की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। तीसरी भाषा के रूप में गैर-भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है, लेकिन शर्त यही है कि बाकी दो भाषाएं भारतीय हों।

कक्षा 10 (2026-27) के मौजूदा छात्रों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें तीसरी भाषा की पढ़ाई या बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी और वे पुराने सिस्टम के अनुसार ही पढ़ाई जारी रखेंगे। वहीं कक्षा 9 के सभी छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है, जबकि तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी या स्पेनिश जैसी गैर-भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है।

2026-27 से नई गाइडलाइंस लागू होंगी

सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कई भारतीय भाषाओं में दक्ष बनाना और भाषा सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, ताकि उनकी शिक्षा संतुलित और समग्र रूप से विकसित हो सके। बोर्ड चाहता है कि भाषा सीखना केवल एक विषय न होकर एक सार्थक, रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव बने, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करे। इसके अलावा, सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 और 10) में तीसरी भाषा को शामिल करना मिडिल स्टेज (कक्षा 6 से 8) में शुरू हुई भाषा सीखने की प्रक्रिया का ही विस्तार है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में भाषा नीति को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करना आवश्यक माना गया है।

कक्षा 9 के छात्रों के लिए थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी

स्थिति 1- अगर आप पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं (जैसे हिंदी और तमिल), तो आप तीसरी भाषा के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषा या कोई गैर-भारतीय भाषा (जैसे अंग्रेज़ी या फ्रेंच) चुन सकते हैं।

स्थिति 2- अगर आप एक भारतीय और एक गैर-भारतीय भाषा पढ़ रहे हैं (जैसे तमिल और अंग्रेज़ी), तो आपको तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा चुननी होगी।

स्थिति 3- अगर आप दो गैर-भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं (जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच), तो 2026-27 के लिए एक विशेष छूट दी जाएगी। आप इन्हें जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़नी अनिवार्य होगी।

केशव पुरम में चार मंजिला इमारत में आग, छत पर फंसे तीन लोग बचाए गए

नई दिल्ली । उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशव पुरम इलाके में सोमवार तड़के एक चार मंजिला इमारत में आग लग गई। आग भूतल पर स्थित बिजली के मीटरों से शुरू हुई। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल गया। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। अंदर फंसे कुछ लोग किसी तरह इमारत से बाहर निकले। वहीं कुछ लोग जान बचाने के लिए छत की ओर भागे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने राहत बचाव अभियान चलाकर छत पर फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला। दमकल विभाग के मुताबिक विभाग को रात 2.03 बजे आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर तुरंत दो वॉटर टेंडर, दो वॉटर बाउजर और एक क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी भेजी गई। दमकल कर्मियों ने छत पर फंसे तीन लोगों गौरव (28), कायरा (25) और इंदु बत्रा (55) को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि आग भूतल पर स्थित बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी, इसमें 24 इलेक्ट्रिक मीटर जलकर राख हो गए।

दिल्ली के अस्पताल से भागा अंडरट्रायल कैदी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार, 48 घंटे में क्राइम ब्रांच ने दबोचा

नई दिल्ली। दिल्ली क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने अस्पताल से भागे एक अंडरट्रायल कैदी को मात्र 48 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पवन भल्ला (26 वर्ष) नामक आरोपी ने रोहिणी के सेंट्रल जेल में जानबूझकर अज्ञात पदार्थ खाकर खुद को बीमार दिखाया। इसके बाद उसे डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। 26 जून की शाम करीब 6-45 बजे आरोपी ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी और वेंटिलेशन होल से भाग निकला। इस घटना के बाद आईपी एस्टेट थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया था इंस्पेक्टर महिपाल सिंह के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने (एसीपी सतेंद्र मोहन के पर्यवेक्षण में) तकनीकी निगरानी, मानवीय खुफिया जानकारी और फील्ड ऑपरेशन के जरिए तुरंत तलाश शुरू की। टीम ने आरोपी को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के जितपुर बेहड़ी इलाके से 28 जून को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मात्र 48 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया। पवन भल्ला को 15 जून को रोहिणी के सेक्टर-4, लाल फ्लैट्स के पास पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया था। उसके पास से प्रतिबंधित बटन वाला चाकू बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पवन भल्ला ने बताया कि अस्पताल से भागने के तुरंत बाद वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़कर ऊना चला गया। वहां अपने पुराने परिचित के घर में छिपा रहा और एक वेयरहाउस में लोडिंग-अनलोडिंग का काम करके अपना गुजारा करता रहा। पवन मूलत हरियाणा के जींद जिले का निवासी है। वह 2023 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और उसके खिलाफ तीन केस दर्ज हैं। वह डीजे सेटअप में हेल्पर और लेबर का काम कर चुका है। उसने ड्रग्स की लत होने की भी बात स्वीकारी है।

दिल्ली में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, मानसून की एंट्री की तारीख तय, गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में इस समय भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है. लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. हालांकि, मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है. विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इन दो दिनों के दौरान तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी. हालांकि, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापक राहत मिलने की संभावना कम है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

30 जून से दिल्ली में एसआईआर की दस्तक, बीएलओ पहुंचेंगे घर-घर; 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग की घंटी बज सकती है। दिल्ली में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार के मुताबिक, पूरे 21 साल बाद दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है।

अगर आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है, या उसमें कोई गलती है, तो आपके पास इसे ठीक कराने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। दिल्ली में लगभग 13 हजार बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) 30 जून से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार में घर पर नहीं मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम आपके घर कम से कम 3 बार विजिट करेगी। मिलेगा न्यूमिरेशन फॉर्म - सर्वे के दौरान आपको दो न्यूमिरेशन फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म आपको भरकर बीएलओ को देना होगा और दूसरा अपने पास संभालकर रखना होगा।

दस्तावेजों का झंझट नहीं- इस फॉर्म को जमा करते समय आपको किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी है सुविधा- यदि आप काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं या शहरी इलाके में हैं, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसका मकसद उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। साथ ही, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए युवाओं के नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट में सुधार और नए नाम जोड़ने का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया है 30 जून घर-घर जाकर डोर-टू-डोर सर्वे और वेरिफिकेशन की शुरुआत।

5 अगस्त वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट (प्रारूप) का प्रकाशन। 7 अक्टूबर सभी सुधारों और दावों के निपटारे के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

21 साल बाद ऐसा क्यों?

इससे पहले दिल्ली में इस स्तर का स्पेशल रिवीजन साल 2002-2004 में हुआ था। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साल 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि लोग पुरानी डिटेल्स भी चेक कर सकें। इसके अलावा, चुनाव आयोग पोलिंग बूथ्स को भी व्यवस्थित कर रहा है और अब एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1,200 से यादा वोटर्स नहीं होंगे, जिससे वोटिंग के दिन लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। जनता की मदद के लिए दिल्ली के सभी जिलों में जल्द ही विशेष कैंप और हेल्पडेस्क भी लगाए जाएंगे।

अशोका एक्सप्रेस की वेबसाइट से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी, एक जुलाई से होगी लागू

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि यह नीति दिल्ली की वर्षों पुरानी प्रदूषण और परिवहन संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल की संस्तुति के बाद यह नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 अगस्त 2031 तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी से आम लोगों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। उन्होंने कहा कि दोपहिया, चारपहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों को भी इस नीति के दायरे में शामिल किया गया है। प्रेसवार्ता की शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सोमवार को नई ईवी पॉलिसी का मसौदा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे बाद में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें की गईं। परिवहन विभाग की सचिव निहारिका ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पॉलिसी का मसौदा उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मंगलवार तक उनकी मंजूरी भी मिल जाएगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर एक लाख रुपये तथा ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20 हजार रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत वर्ष एक जनवरी 2027 से नए तीनपहिया और वर्ष अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। साथ ही डिस्कॉम के साथ मिलकर घरों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचे नहीं जा सकेंगे। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी से राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने लोगों से इस नीति को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि परिवहन विभाग ने इसे तैयार करने में व्यापक मेहनत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। परिवहन विभाग को इस नीति के क्रियान्वयन का नोडल विभाग बनाया गया है। नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक दोपहिया, ऑटो और मालवाहक वाहनों के लिए चरणबद्ध खरीद सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। दोपहिया वाहन पर पहले वर्ष अधिकतम 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50 हजार रुपये और एन1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक पर पहले वर्ष एक लाख रुपये तक की खरीद सब्सिडी मिलेगी। निजी इलेक्ट्रिक कारों पर खरीद सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन पुराने बीएस-4 या उससे नीचे के वाहन को स्क्रैप करने पर एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को कोई टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट नहीं मिलेगी।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र
प्रिय पाठक, विज्ञापन दाता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email: ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206
अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।
Account Holder Name ASHOKA EXPRESS
Bank Account No.
IFSC Code
UPI ID

नई आपराधिक न्याय व्यवस्था लागू होने की दूसरी वर्षगांठ से पहले हरियाणा ने रचा इतिहास, 95 अंक हासिल कर बना नंबर-1 राज्य

पंचकूला । नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हरियाणा ने देशभर में एक नई मिसाल कायम की है। हरियाणा, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्धारित 95 अंकों के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि को राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीक आधारित कार्यप्रणाली का परिणाम माना जा रहा है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि हरियाणा ने निर्धारित सभी प्रमुख मानकों को पूरा करते हुए 95 अंकों का लक्ष्य हासिल कर लिया। डीजीपी सिंघल ने आगे बताया कि इस उपलब्धि के साथ हरियाणा ने यह संदेश दिया है कि न्याय व्यवस्था में सुधार और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से अपराधों की जांच में तेजी, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे, जिनके तहत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून लागू किए गए। इनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हरियाणा की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों की दूसरी वर्षगांठ से पहले मिली यह सफलता राज्य की प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

फरीदाबाद में कारोबारी ने किया सुसाइड, इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

फरीदाबाद । फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में गारमेंट की दुकान चलाने वाले 28 वर्षीय कारोबारी ने अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले कारोबारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। मृतक की पहचान हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर-3 निवासी राहुल (28) के रूप में हुई है। वह सेक्टर-3 में गारमेंट की दुकान चलाता था, जिसे उसने करीब चार महीने पहले शुरू किया था। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह राहुल घर से अपनी मां से मिलकर दुकान पहुंचा था। कुछ देर बाद उसने दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार राहुल ने करीब

दो वर्ष पहले ज्योति नाम की युवती से लव मैरिज की थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद पत्नी नहीं चाहती थी कि राहुल अपने माता-पिता के साथ रहे। इसी वजह से वह अलग रहने लगा था। हाल ही में उसने अपनी नई गारमेंट की दुकान भी शुरू की थी। मृतक के परिजन अमित ने आरोप लगाया कि राहुल काफी समय से अपनी पत्नी और उसके मायके पक्ष की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान था। उनका कहना है कि पत्नी ने राहुल के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, जिससे वह तनाव में रहने लगा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि राहुल को अपने माता-पिता से मिलने तक से रोका जाता था। आत्महत्या से पहले राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी ज्योति, सास वीना, ससुर बिट्टू और पत्नी की बहन नीतू पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में राहुल ने दावा किया कि वह पत्नी के लिए घर के सभी काम झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करता था, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की जाती थी और उस पर झूठे मामले दर्ज कराए गए। उसने कहा कि वह लगातार मानसिक तनाव में था। वीडियो में राहुल ने यह भी कहा कि उसके इस कदम के लिए पत्नी और ससुराल पक्ष जिम्मेदार हैं तथा उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उसने अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति मां, बहन और भाइयों के नाम होने की बात भी कही। जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर आईटीआई छात्रों को हर महीने 2000 रुपये... हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित करने की तैयारी में है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की पहल की है। बता दें कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र तकनीकी प्रशिक्षण बीच में न छोड़े। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से आईटीआई में दाखिले बढ़ेंगे, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र में हरियाणा के 377 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 197 सरकारी और 180 निजी ITI शामिल हैं। इन संस्थानों में करीब एक लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 89 से अधिक इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण का विकल्प मिलेगा, जिनमें पारंपरिक ट्रेडों के साथ आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। सरकार इस समय ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) पर विशेष जोर दे रही है। इस मॉडल में विद्यार्थियों को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान ही उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है। मशीनों पर काम करने, उत्पादन प्रक्रिया समझने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और औद्योगिक कार्यप्रणाली सीखने का अवसर मिलने से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देकर प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रमों को उद्योग आधारित बनाया जा रहा है। इससे प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और राज्य को कुशल कार्यबल भी मिलेगा।

हरियाणा के जल अधिकारों का सौदा नहीं होने देंगे, एक-एक बूंद की रक्षा के लिए लड़ेगी इनेलो - प्रो. संपत सिंह

चंडीगढ़ ।

पूर्व वित्त मंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि इनेलो हमेशा हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और राज्य के यमुना जल में उसके वैधानिक हिस्से पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली में आज बीजेपी ने जो हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौता किया है इसका इनेलो पूरजोर विरोध करती है। दूसरी ओर, एस.वाई.एल. नहर का निर्माण भी सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद अधूरा है, जिससे हरियाणा को लगातार जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हरियाणा के पानी के मामले में एक हो चुकी है। कांग्रेस ने जैसे कुर्सी बचाने के लिए समझौता किया था उसी तर्ज पर आज बीजेपी सरकार ने राजस्थान को पानी देने का समझौता किया है। हरियाणा का पानी हरियाणा का है। इनेलो उसकी एक-एक बूंद की रक्षा

के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि 12 मार्च, 1954 को तत्कालीन पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच हुए यमुना जल समझौते में पूर्वी एवं पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से पंजाब के अधिकार को मान्यता दी गई थी।

वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद यह अधिकार हरियाणा को प्राप्त हुआ। कई दशकों तक लगभग 12 बीसीएम यमुना जल का उपयोग हुआ, जिसमें हरियाणा लगभग 8 बीसीएम तथा उत्तर प्रदेश लगभग 4 बीसीएम जल का उपयोग करता रहा। किन्तु 12 मई, 1994 को केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए नए समझौते के तहत हरियाणा का हिस्सा घटाकर 5.730 बीसीएम कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को 4.032 बीसीएम, राजस्थान को 1.119 बीसीएम, दिल्ली को 0.724 बीसीएम तथा हिमाचल प्रदेश को 0.378 बीसीएम आवंटित किया गया। इससे हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत रह गई। इससे पहले राजस्थान और दिल्ली को केवल अतिरिक्त उपलब्ध जल मानवीय आधार पर दिया जाता था, जिसे 1994 के समझौते ने स्थायी आवंटन का रूप दे दिया। प्रो. संपत सिंह ने कहा कि इसी समझौते में यमुना जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेणुका, किशाऊ तथा लखवार-व्यासी बांधों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन तीन दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ये परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि 1978 की भीषण बाढ़ के बाद 1989 में साहिबी, कृष्णावती एवं अन्य मौसमी नदियों के जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने लगभग 69 करोड़ रुपये की लागत से मसानी जलाशय का निर्माण कराया। बाद में राजस्थान ने ऊपरी क्षेत्र में कच्चे बांध बनाकर प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया, जिससे हरियाणा की सिंचाई क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पुराने विवादों का समाधान करने के बजाय वर्तमान भाजपा सरकार राजस्थान के साथ ऐसे नए समझौते कर रही है, जो हरियाणा के हितों को और कमजोर करते हैं। प्रो. संपत सिंह ने कहा कि 1994 में स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में यमुना जल समझौते के विरोध में इनेलो के सभी 17 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसे हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बलिदान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हरियाणा के वैध जल अधिकारों की प्रभावी रक्षा करने में विफल रही हैं। इनेलो लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। प्रो. संपत सिंह ने बताया कि शीघ्र ही चैधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी कदम का फैसला किया जाएगा।

फुकुओका, जापान की 80 प्रतिशत कंपनियों में मानव संसाधन की भारी कमी, हरियाणा के 50 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका

चंडीगढ़ । जापान के फुकुओका में तकनीकी क्षेत्र की 80 प्रतिशत कंपनियों, जिनमें सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, आईटी तथा अन्य निर्माण इकाइयां शामिल हैं, को इस समय तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा सरकार से यहां के युवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अनुरोध किया है ताकि अगले पांच साल में यहां के 50 हजार युवाओं को फुकुओका प्रीफेक्चर में रोजगार उपलब्ध करवाकर मानव संसाधन की कमी को दूर किया जा सके। हरियाणा सरकार और जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर के बीच औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में सोमवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में 'हरियाणा-फकुओका कनेक्ट-2026' के अंतर्गत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में फुकुओका प्रीफेक्चर सरकार, फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार, विश्वविद्यालयों व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर मंथन किया। इबैठक के दौरान हरियाणा और फुकुओका के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, निवेश संभावनाओं, तकनीकी मानव संसाधन तथा शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने भारतीय युवाओं, विशेषकर हरियाणा के 50 हजार विद्यार्थियों और तकनीकी पेशेवरों के लिए अगले पांच साल में जापान में रोजगार, इंटर्नशिप तथा कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इहरियाणा के विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं तथा जापानी कंपनियों के लिए विकसित किए जा रहे विशेष औद्योगिक इकोसिस्टम की जानकारी दी। राज्य सरकार ने निवेशकों को त्वरित अनुमतियां, सिंगल विंडो प्रणाली तथा उद्योग-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जापान की यात्रा कर विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इसके साथ ही जापान के साथ आपसी समन्वय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होने बताया कि हरियाणा और जापान को इतिहास, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में भी आदान-प्रदान की जरूरत है ताकि दोनों क्षेत्र एक-दूसरे को अच्छी प्रकार समझ सकें। उन्होंने ग्रीन जॉब्स तथा ग्रीन फ्यूल्स आदि क्षेत्रों में भी मिलकर कार्य करने की जरूरत पर बल दिया। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा और फुकुओका के बीच सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए 'हरियाणा सकुरा वर्किंग ग्रुप' का गठन किया गया है जिसके माध्यम से फुकुओका आधारित कंपनियों और संस्थानों की सहायता के लिए एक 'समर्पित हेल्प डेस्क' भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी फुकुओका की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को तैयार करने में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि हरियाणा के अधिक से अधिक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से तथा एचकेआरएन के सहयोग से हरियाणा के उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फुकुओका में मानव संसाधन की कमी की पूर्ति करने का अवसर मिलेगा।

लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक सहित दो निलंबित, दो को किया लाइन हाजिर

कुशीनगर।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार ने रात्रि चेकिंग एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और शिथिलता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। जनहित एवं प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रभारी निरीक्षक कसया सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो को निलंबित तथा दो को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कसया निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह एवं थाना कसया में तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं थाना तरयासुजान के चौकी प्रभारी बहादुरपुर उपनिरीक्षक धर्मवीर सिंह तथा चौकी प्रभारी तिनफेडिया उपनिरीक्षक शिवम द्विवेदी को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है। क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. अजय कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारी कसया का दायित्व सौंपा गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अपराध राकेश प्रताप सिंह को क्षेत्राधिकारी सदर की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा की गई इस कार्रवाई को विभाग में अनुशासन, जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

रामनाम के जयघोष संग निकला नगर भ्रमण, भक्तिमय हुआ वातारण

पटहेरवा कुशीनगर।

- बेलही कुटी से निकली शोभायात्रा विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कर दुर्गा स्थान पहुंची
- आज भजन-कीर्तन, महाभंडारा, लोकगीत और भव्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन

तमकुही विकास खंड के सेमरा हर्दोपट्टी के बेलही कुटी स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ सोमवार को भव्य नगर भ्रमण के साथ हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। धार्मिक ध्वज, जयघोष और भक्ति गीतों के बीच निकली शोभायात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया।

मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया तथा भगवान के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आयोजक एवं महंत बाबा बालक दास उर्फ श्यामदास के नेतृत्व में बेलही कुटी से नगर भ्रमण प्रारंभ हुआ। शोभायात्रा सबसे पहले सेमरा हर्दोपट्टी के हनुमत कथा कुंज पहुंची। वहां दर्शन-पूजन के बाद श्रद्धालु राधाकृष्ण मंदिर, खलवापट्टी और तारविशुनपुर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इसके बाद शोभायात्रा गुरवलिया बाजार और गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए झरही नदी तट स्थित दुर्गा स्थान पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे और भगवान श्रीराम व बजरंगबली के जयघोष से वातावरण गुंजायमान बना रहा।

दुर्गा स्थान पहुंचने पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद अखंड कीर्तन का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देर तक चले भजन-कीर्तन में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे। आयोजन स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे और श्रद्धालुओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराते रहे।

महंत बाबा बालक दास उर्फ श्यामदास ने बताया कि आयोजन के दूसरे दिन मंगलवार को हनुमंत आराधना, सुंदरकांड पाठ, भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण और महाभंडारा आयोजित किया जाएगा। दिन में प्रसिद्ध लोकगायक सत्या पांडेय नादान तथा लोकगायिका काजल सिंह भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर करेंगे। सायं छह बजे से रात्रि 10 बजे तक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कवि बादशाह प्रेमी सहित अन्य कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे सियाराम दास, शिवदास, हेमनरायण, ज्ञानप्रकाश पांडेय, सिकन्दर शर्मा, दुर्गेश सिंह, हेमंत सिंह, वीरेश सिंह, मुन्ना सिंह, दिलीप सिंह, चंदन सिंह, जयप्रकाश सिंह, नंदलाल पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

जनता दर्शन में कड़ा रुखः फाइलों के निस्तारण में ढिलाई पर डीएम ने अफसरों को चेताया

देवरिया।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे संदीप का प्राथमिकता पर बनेगा अंत्योदय व आयुष्मान कार्ड
पारिवारिक विवाद से पीड़ित महिला की मदद के लिए पुलिस बल के साथ मौके पर जाएगी टीम

जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सुदूर ग्रामीण अंचलों से पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की। कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दफ्तरों में लेटलतीफी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को हर तरह की शासकीय पत्रावलियों का प्रेषण अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही करने के कड़े निर्देश दिए। जनता दर्शन के दौरान दो प्रमुख मामले प्रशासनिक संवेदनशीलता के केंद्र में रहे। सलेमपुर तहसील के मठिया इंदौली ग्राम निवासी संदीप कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि पिता की गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार भारी संकट में है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) को प्राथमिकता के आधार पर संदीप का अंत्योदय राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, गोबराई गांव की पुष्पा देवी ने अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा घर से बेदखल किए जाने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सदर को निर्देश दिया कि वे राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और स्थानीय थाने के पुलिस बल की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजें और पीड़ित महिला को न्याय सुनिश्चित कराएं। मुख्यालय पर उमड़ी फरियादियों की भीड़ की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिले के समस्त जनपद स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यालयों में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनें। जो भी प्रकरण जिस स्तर का हो, उसे तय समय सीमा के भीतर हल किया जाए ताकि पीड़ितों को बार-बार जिला मुख्यालय की दौड़ न लगानी पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी पटल पर लापरवाही के कारण जनशिकायतें लंबित पाई गईं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक शासकीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलेक्ट्रेट के इस सख्त रुख से प्रशासनिक हलकों में मुस्तैदी बढ़ गई है।

अचानक गिरा 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार, राहगीरों में दहशत

बांसी,सिद्धार्थनगर।

तार गिरते ही आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि तार उस छोर से टूटा जहाँ से बिजली का मुख्य प्रवाह नहीं था, वरना व्यस्त सड़क पर कोई बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था।यह घटना लगभग 8 बजे की है स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है।

नगर पालिका परिषद बांसी के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक कोतवाली रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब अचानक 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर बीच सड़क पर आ गिरा। तार गिरते ही आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि तार उस छोर से टूटा जहाँ से बिजली का मुख्य प्रवाह नहीं था, वरना व्यस्त सड़क पर कोई बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था।यह घटना लगभग 8 बजे की है स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कोतवाली रोड नगर का सबसे प्रमुख और अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग है। जब मुख्य मार्ग पर जर्जर तारों की यह स्थिति है, तो अंदरूनी मोहल्लों और पूरे नगर की विद्युत व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दुकानदारों का आरोप है आए दिन यहाँ जर्जर तारों के टूटने और फॉल्ट होने की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। विभाग का पूरा ध्यान सिर्फ जनता से वसूली करने पर है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बुनियादी सुधारों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर बिजली विभाग की मेंटेनेंस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। व्यस्त बाजार में हाईवोल्टेज तार का इस तरह गिरना प्रशासनिक उदासीनता का जीता-जागता सबूत है। स्थानीय जनता अब यह सवाल उठा रही है कि क्या बिजली विभाग और जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी जनहानि के बाद ही कुंभकर्णी नींद से जागेंगे। इस दौरान दुकान दार छोटे भाई, नरेश कुमार चंदवानी,घंश्याम हाडवेयर, दिनेश विश्वकर्मा, स्टार मेडिकल मौजूद रहे।

संचारी रोगों के खिलाफ कलेक्ट्रेट की बड़ी घेराबंदी- लापरवाही पर रुकेगा वेतन, डीएम सख्त

देवरिया।

1 से 31 जुलाई तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान
थ्री-ए की सुस्ती पर होगी सीधी कार्रवाई; निजी भवनों के बजाय अब सरकारी परिसरों में होंगे स्वास्थ्य सत्र

जुलाई महीने से शुरू हो रहे संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को धरातल पर प्रभावी बनाने तथा स्वास्थ्य योजनाओं को पारदर्शी ढंग से आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग सहित इससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों को समन्वय और मैदानी मुस्तैदी का पाठ पढ़ाया। जिलाधिकारी ने दोटूक निर्देश जारी किए हैं कि अभियान के दौरान फील्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी और संबंधित कर्मियों के खिलाफ सीधे वेतन रोकने जैसी कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत ग्रामीण और शहरी अंचलों में साफ-सफाई, जलभराव की तात्कालिक निकासी, नालियों में एंटी-लार्वा के नियमित छिड़काव और सघन जनजागरूकता पर सबसे यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। जिलाधिकारी ने नगरीय व ग्रामीण निकायों को आबादी वाले क्षेत्रों से सूअर बाड़ों को दूर रखने तथा मुर्गी फार्मों में स्वच्छता के कड़े मानक लागू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी रीढ़ माने जाने वाले ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) सत्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि थ्री-ए यानी आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम अपने आवंटित क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सक्रिय रहकर कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देशित किया कि वे निजी स्थानों पर संचालित होने वाले स्वास्थ्य सत्रों को तत्काल प्रभाव से सरकारी भवनों में स्थानांतरित कराएं और वहां आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए बाल विकास पुष्टाहार (आईसीडीएस) विभाग को हाई-रिस्क जोन में कुपोषित बचों को चिन्हित कर उन्हें पोषण सेवाओं से जोड़ने और शत-प्रतिशत प्रसव (डिलीवरी) रिपोर्ट की सटीक ट्रैकिंग करने को कहा गया है, ताकि कोई भी मामला मिसिंग सूची में न जाए। संचारी रोगों के साथ ही क्षय रोग (टीबी) नियंत्रण कार्यक्रम को भी पूरी गंभीरता से संचालित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट के इस सख्त रुख से साफ है कि आगामी एक महीने तक पूरा प्रशासनिक अमला फील्ड में सक्रिय रहेगा।

जिसका डर था, वही हुआ! महिला टी20 विश्वकप से टीम इंडिया आखिर क्यों हुई बाहर? ये रहे छह सबसे बड़े कारण

लंदन । भारतीय महिला क्रिकेट टीम का टी20 विश्वकप में सफर खत्म हो गया। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज में हार ने भारत के सफर को रोक दिया। टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। महिला टी20 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज रहीं। अब टीम इंडिया की हार के बाद फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। खासतौर पर पिछले साल वनडे विश्वकप जीतने के बाद टीम इंडिया से काफी उम्मीदें थीं। भारतीय महिला टीम के पास अनुभवी बल्लेबाज, विश्व स्तरीय स्पिन आक्रमण और बड़े मंच का अनुभव था, लेकिन आधुनिक टी20 क्रिकेट की सबसे अहम जरूरतें, आक्रामक रणनीति, प्रभावी तेज गेंदबाजी, दमदार फील्डिंग और दबाव में सही फैसले, पूरे टूर्नामेंट में कमजोर साबित हुईं। यही कारण रहा कि भारत अच्छी शुरुआत और कुछ जीत के बावजूद सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका।

1. बड़े मुकाबलों में रणनीति ही उलटी पड़ गई

कोच अमोल मजूमदार और कप्तान हरमनप्रीत कौर दोनों ने स्वीकार किया कि टीम को अपनी टी20 रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि उसी पिच पर रन बनाना आसान नहीं था। 170 रन को टीम ने पर्याप्त माना, लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य का स्पष्ट अंदाजा मिल गया। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव आ गया कि वे मजबूत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के खिलाफ इस स्कोर का बचाव करें। अनुभवी बल्लेबाजी क्रम पर दबाव कम करने की कोशिश आखिरकार टीम के खिलाफ चली गई।

2. तेज गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई

स्पिनरों ने लगातार विकेट निकाले, लेकिन तेज गेंदबाज लगभग बेअसर रहे। पूरे टूर्नामेंट में भारत के पेस अटैक ने सबसे कम सिर्फ 2 विकेट लिए। उनका गेंदबाजी औसत 64.50, स्ट्राइक रेट 45.5 और इकॉनमी 8.50 रही, जो प्रतियोगिता में सबसे खराब आंकड़ों में शामिल रही। भारतीय तेज गेंदबाज शुरुआती विकेट नहीं निकाल सके और न ही बल्लेबाजों पर दबाव बना पाए। इससे स्पिनरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बढ़ गई।

3. फील्डिंग ने बार-बार मेहनत पर पानी फेर दिया

भारत की फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में चिंता का विषय रही। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों के भीतर चार कैच छूटे। पाकिस्तान के खिलाफ भी तीन मौके गंवाए गए। 2025 के बाद भारत ने 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 46 कैच छोड़े, जो इस अवधि में किसी भी टीम से सबसे ज्यादा हैं। टीम की कैचिंग एफिशिएंसी केवल

69.3 प्रतिशत रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मान चुकी हैं कि बड़े मुकाबलों में ऐसी गलतियां मैच का रुख बदल देती हैं।

4. बल्लेबाजी में सही समय पर सही फैसले नहीं हुए

भारत का बल्लेबाजी क्रम पूरे टूर्नामेंट में स्थिर नहीं दिखा। अलग-अलग मैचों में मध्यक्रम की बल्लेबाजी क्रम बदलती रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिग्स लंबे समय तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन उन्हें काफी देर से रिटायर्ड आउट किया गया। तब तक सिर्फ कुछ ओवर बचे थे और विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष को केवल एक गेंद खेलने का मौका मिला। टीम की आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति बड़े मैच में डिफेंसिव सोच में बदल गई।

5. डेथ ओवरों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों फेल

भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में आखिरी ओवरों में दबाव झेलने में असफल रही। गेंदबाजी में डेथ ओवरों में लगातार बड़े रन दिए गए, जबकि बल्लेबाजी में लक्ष्य का पीछा करते समय जरूरी रन गति हासिल नहीं हो सकी। हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकार किया कि लंबे समय से यही समस्या बनी हुई है कि टीम मैच में रहते हुए भी अंतिम ओवरों में मुकाबला गंवा देती है।

6. सही प्लेइंग-11 नहीं मिल पाया

विश्वकप के दौरान भारत लगातार अपने सही संयोजन की तलाश में रहा। पांच मैचों में तेज गेंदबाजों के अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाए गए। श्रेयंका पाटिल की चोट के बाद डेथ ओवरों में विकल्प नहीं मिला। कोच अमोल मजूमदार ने भी माना कि टीम अब तक तय नहीं कर सकी कि उसका सर्वश्रेष्ठ टी20 संयोजन क्या है। यही असमंजस पूरे अभियान में दिखाई दिया।

जिन दो मैचों का डर था, उन्हीं में हारे

सारे एनालिसिस के बाद भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही रहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिन दो बड़े मुकाबलों को सबसे अहम माना जा रहा था, आखिरकार वही टीम की किस्मत तय कर गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला ऐसा था, जिसमें जो टीम उस दिन बेहतर खेलती, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा थी और हुआ भी बिल्कुल यही। भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ जीत जरूर दर्ज की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी।

एक दिन के अच्छे खेल से चमकी द. अफ्रीका की किस्मत

दिलचस्प बात यह भी रही कि दक्षिण अफ्रीका का अभियान भी डगमगाता रहा है।

टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ संघर्ष करती नजर आई और ग्रुप चरण के अंत तक उसे अपनी उम्मीदों के लिए ऑस्ट्रेलिया के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ा। इसके बावजूद ग्रुप-ए का फैसला उस टीम के पक्ष में गया, जिसने 21 जून को कम गलतियां कीं। भारत के लिए छूटी हुई कैच सबसे महंगी साबित हुईं। फील्डिंग में हुई चूकों का दक्षिण अफ्रीका ने पूरा फायदा उठाया। मारीजाने कैप की शानदार पारी ने मैच का रुख बदल दिया और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका बेहतर टीम साबित हुई।

गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कमियां रहीं हार की जड़

इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमियां दिखीं। बल्लेबाजी में भी कई सवाल बने हुए हैं।

महिला प्रीमियर लीग के चार सीजन पूरे होने के बावजूद कोई घरेलू बल्लेबाज ऐसा दावा पेश नहीं कर सका है, जो जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में कड़ी चुनौती दे सके। संभव है कि डब्ल्यूपीएल में टीमें इस तरह स्ट्रैटजी बनाती हैं कि भारतीय घरेलू बल्लेबाजों को शीर्ष क्रम में पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल टीम को अपने मौजूदा बल्लेबाजों से ही प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद करनी होगी। यह विश्व कप अभियान साफ संकेत देता है कि भारतीय महिला टीम को बदलाव की जरूरत है। इस बात से खुद अमोल मुजुमदार भी सहमत हैं। हालांकि, उन्होंने कई बार रीथिंक यानी नई रणनीति पर विचार करने की बात कही, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि बदलाव आखिर होगा किस स्तर पर। इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं हैं। फिलहाल भारतीय टीम विश्व कप की निराशा को पीछे छोड़कर अगले बड़े लक्ष्य की तैयारी करेगी। दो सप्ताह बाद इसी मैदान पर महिला क्रिकेट इतिहास का एक और अहम अध्याय लिखा जाएगा, जब लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा।

भारत की हार पर गौतम गंभीर का उड़ा मजाक- आइसलैंड क्रिकेट के तंज ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

बेलफास्ट । आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए हैं। भारत की इस अप्रत्याशित हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने भी अपने मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट कर टीम इंडिया और गंभीर पर तंज कसा, जो तेजी से वायरल हो गया। आयरलैंड ने इस सीरीज में इतिहास रचते हुए पहली बार भारत को किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हराया। इसके साथ ही भारत की लगातार 16 टी20 द्विपक्षीय सीरीज जीतने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। यह अजेय क्रम लगभग तीन वर्षों से जारी था। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गौतम गंभीर पर व्यंग्य किया। पोस्ट में लिखा गया, हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि, उनमें प्रतिभा जरूर है। आयरलैंड में इतने शानदार भारतीय खिलाड़ियों के रहते हुए ऐसे शानदार नतीजे हासिल करना वास्तव में असाधारण क्षमता की बात है। यह पोस्ट भारत की स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम पर भी कटाक्ष था, जिसमें संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे टी20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी शामिल थे। इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजी आयरलैंड के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने दोनों मुकाबलों में संघर्ष करती नजर आई। गौतम गंभीर ने 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में भारत ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया था। टीम ने श्रीलंका और बांग्लादेश को 3-0 से हराया, दक्षिण अफ्रीका में 3-1 से सीरीज जीती, इंग्लैंड को 4-1 और न्यूजीलैंड को 4-1 से मात दी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी भारत ने 2-1 से टी20 सीरीज अपने नाम की थी। हालांकि, आयरलैंड दौरे पर यह विजयी अभियान थम गया और गंभीर के कोच बनने के बाद भारत को पहली बार किसी टी20 द्विपक्षीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। भारत का यह आयरलैंड दौरा 2023 के बाद पहला था। इससे पहले दोनों टीमें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आठ बार भिड़ी थीं और हर बार भारत ने जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत 2024 टी20 विश्व कप में हुई थी, जहां भी भारत विजयी रहा था। लेकिन इस बार आयरलैंड ने पहले टी20 में 34 रन से जीत दर्ज कर भारत के खिलाफ अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जीता। इसके बाद दूसरे मैच में एक रन से रोमांचक जीत हासिल कर उसने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। यह आयरलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।

भारत को क्लीन स्वीप करने पर क्या बोले जय मूंदड़ा? जीत के पीछे की आयरलैंड की रणनीति का किया खुलासा

बेलफास्ट। आयरलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत में जन्मे इस खिलाड़ी ने सीरीज के पहले मैच में 25 रन देकर दो विकेट, जबकि अगले मुकाबले में 32 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है, जिसके बाद जय ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का उनका पहला अनुभव शानदार रहा। मूंदड़ा ने रविवार को सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को मुश्किल में डाल दिया।

उन्होंने संजू सैमसन को पगबाधा आउट किया और फिर अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन भेजा। जय ने कुल तीन विकेट लिए और आयरलैंड ने एक रन से जीत हासिल कर यादगार सीरीज अपने नाम की। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जय ने कहा, %मैं अभी भी इस एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि

इसे एक शब्द में बताना मुश्किल है। बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना और खुद को परखना एक शानदार एहसास है। तो बस लंबे समय तक बुनियादी चीजें करना ही योजना थी। टीम के सदस्यों और मैनेजमेंट को इसका श्रेय जाता है।

चीजों को आसान रखना। मुश्किल समय आएगा, लेकिन शांत और संयमित रहकर अपना काम करते रहना है। मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। सैमसन के खिलाफ गेंदबाजी करते समय अपनी सोच के बारे में मूंदड़ा ने कहा, बस चीजों को आसान रखो, वही करो जो करते आ रहे हो। यह मुश्किल होने वाला है, गलती की गुंजाइश कम है। तो बस वही करते रहो जो तुम करते आ रहे हो और प्लान पर टिके रहो। साल 2021 में आयरलैंड आने के बाद टीम में अपनी जगह बनाने के दौरान आई मुश्किलों पर बात करते हुए मूंदड़ा ने कहा, खैर, हर किसी की जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, तो बस आपको डटे रहना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। और कुछ नहीं।

बुद्धम् शरणम् गच्छामि-कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बुद्ध विहार में किया दर्शन-पूजन

नई दिल्ली (ए,के,चौधरी)कांग्रेस के राष्टीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने आज मंदिर मार्ग, दिल्ली,स्थित बुद्ध विहार में दर्शन-पूजन कि। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहे।

पौधा भेंट कर किया स्वागत, देवेंद्र यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए यह भेंट की गई। श्री खरगे ने दर्शन के बाद कहा, ÷बुद्धम् शरणम् गच्छामि। भगवान बुद्ध की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है।÷ उन्होंने देश में शांति, सद्भाव और करुणा के लिए प्रार्थना की।

देवेंद्र यादव ने कहा,दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया, द्÷आज हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ मंदिर मार्ग स्थित बुद्ध विहार में दर्शन-पूजन का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं। इस दौरान बुद्ध विहार में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भी मौजूद रहे। छाया ~ सहित गौड़, दैनिक, सक्षम भारत

2031 तक टाटा मोटर्स लाएगी चार नई इलेक्ट्रिक कारें; ग्रीस पहुंचा भारतीय उद्यमी प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली । टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2031 तक चार नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने और मौजूदा पोर्टफोलियो के 10 से अधिक मॉडल को फेसलिफ्ट एवं अपग्रेड करने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा, उसका लक्ष्य भारतीय बाजार में 30 फीसदी से अधिक ईवी गाड़ियां उतारना है। फिलहाल टाटा की छह ईवी कार हैं। यूके दौरे के बाद केंद्रीय वाणिय एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल अब ग्रीस पहुंच गया है। इसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और रणनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अब भारत ग्रीस के साथ रक्षा, खाद्य, आधारभूत ढांचा एवं कृषि समेत कई क्षेत्रों में कारोबार-निवेश के अवसर तलाशेगा । ग्रीस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर स्टार्टअप सत्रों में भाग लेगा। एथेंस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए भारतीय और यूनानी उद्योग जगत के नेताओं के साथ निजी क्षेत्र की साझेदारियों को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। दोनों देशों के प्रमुख हितधारकों की भागीदारी वाला एक उच्चस्तरीय व्यापारिक संवाद भी आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के प्रमुख उद्योग प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेगा, जहां उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस कवायद का मकसद भारत-ग्रीस द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना बताया जा रहा है। इस पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूके की यात्रा कर प्रस्तावित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को लागू करने के तरीकों पर वहां के मंत्रियो व अधिकारियों के साथ बात की।

कमोडिटी ईटीएफ में प्राइस डिस्कवरी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से लागू होगा बदलाव

(वेबवार्ता)

अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में पैसा लगाते हैं, तो आगामी 1 सितंबर 2026 से ट्रेडिंग के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब तक अक्सर देखा जाता था कि जब अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में रात के समय बड़ी उठापटक होती थी, तो भारतीय ईटीएफ बाजार अगले दिन तुरंत उस बदलाव को सही तरीके से नहीं दिखा पाते थे। इसी विसंगति को दूर करने और निवेशकों को हकीकत के करीब लाने के लिए बाजार नियामक सेबी प्री-ओपन कॉल ऑक्शन मैकेनिम और डायनेमिक प्राइस बैंड का नया फॉर्मूला लेकर आया है। नए नियमों के तहत कमोडिटी ईटीएफ (खासकर गोल्ड और सिल्वर फंड्स) के लिए ट्रेडिंग की शुरुआत प्लस/माइनस 6न्न के शुरुआती प्राइस बैंड के साथ होगी। यदि बाजार में उतार-चढ़ाव बहुत तेज होता है, तो एक निश्चित कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद इस प्राइस बैंड को 3-3 फीसदी के दायरे में और आगे बढ़ाया जा सकेगा। मौजूदा सिस्टम के विपरीत, अब नए नियमों में इस बात की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी कि एक ही ट्रेडिंग

सेशन के दौरान इस बैंड को कितनी बार चौड़ा किया जा सकता है। इससे कीमतों में होने वाले वैश्विक उतार-चढ़ाव को तुरंत भारतीय बाजारों में एडजस्ट किया जा सकेगा। सेबी ने ईटीएफ की आधार कीमत तय करने के तरीके में भी सुधार किया है। सितंबर 2026 से, पिछले कारोबारी दिन के आखिरी 30 मिनट के क्लोजिंग प्राइस को ही संदर्भ मूल्य माना जाएगा। इससे बाजार के उतार-चढ़ाव के दौरान अचानक से दिखने वाले भारी प्रीमियम या डिस्काउंट को कम करने में मदद मिलेगी।

निवेशकों को फायदे?

इसका सबसे बड़ा फायदा बेहतर मूल्य पारदर्शिता और निष्पक्ष निष्पादन होगा। यह नया तंत्र बाजार सहभागियों को नियमित कारोबार शुरू होने से पहले अधिक सटीक शुरुआती कीमत खोजने की अनुमति देगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में रातों-रात जो भी उतार-चढ़ाव होगा, वह अगले दिन सुबह भारतीय ईटीएफ निवेशकों को अधिक सटीक रूप से दिखाई देगा। नया प्राइसिंग मैकेनिम और प्री-ओपन ऑक्शन सिस्टम मार्केट में कृत्रिम रूप से बढ़ने या घटने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट को रोकेगा, जिससे आम निवेशकों को सही कीमत पर यूनिट्स मिलेंगी। डायनेमिक बैंड होने से बड़े संस्थागत निवेशकों और मार्केट मेकर्स को ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, जिससे बाजार में तरलता बढ़ेगी। निवेशकों को कम मूल्य विस्थापन, बेहतर तरलता, ईटीएफ कीमतों और एनएवी के बीच बेहतर तालमेल, और तर्कहीन कीमतों पर घबराहट के कारण होने वाली खरीद या बिक्री की कम संभावनाओं के माध्यम से लाभ होने की उम्मीद। हालिया सुधार को मुख्य रूप से मुनाफावसूली और बदलती व्यापक आर्थिक उम्मीदों के संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक संरचनात्मक मंदी की शुरुआत के रूप में। चांदी का उपयोग सोलर पैनलों, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे संरचनात्मक मांग को समर्थन मिलता है। सोना-चांदी अनुपात, जो 100 से ऊपर से गिरकर लगभग 66 पर आ गया है, चांदी के हालिया बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। चांदी की आपूर्ति सीमित बनी हुई है और मांग का आउटलुक मजबूत है। 2 से 5 साल के नजरिये से चांदी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। मौजूदा निवेशकों के लिए, यह घबराहट में बिकवाली करने का चरण नहीं है। दीर्घकालिक निवेशक अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं, जबकि एसआईपी निवेशकों को अपना व्यवस्थित निवेश जारी रखना चाहिए। नए निवेशक एकमुश्त निवेश के बजाय धीरे-धीरे खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं।

बढ़ती कीमतों और अनिश्चितताओं के बीच आवासीय बिक्री में 6फीसदी की गिरावट - एनारॉक

(वेबवार्ता)

नई दिल्ली। देश के सात प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आवासीय बिक्री छह प्रतिशत घटकर 90,715 इकाई रह गई। आर्थिक अनिश्चितता और मकानों की बढ़ती कीमतें इसकी प्रमुख वजह रही। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनारॉक की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में पिछले वर्ष की समान अवधि में कुल आवासीय बिक्री 96,285 इकाई रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन सातों शहरों में 2025 की समान अवधि की तुलना में चालू तिमाही में मकानों की औसत कीमत में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि एनारॉक के अप्रैल-जून तिमाही के बिक्री आंकड़े हाल ही में सूचीबद्ध कंपनी प्रॉपइक्विटी की रिपोर्ट से पूरी तरह अलग हैं। प्रॉपइक्विटी ने चालू तिमाही में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 1,12,458 इकाई होने का दावा किया था। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये आंकड़े अपेक्षित रुझान के अनुरूप हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न बाधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटीईएस क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण अधिक खरीदार फिलहाल खरीदारी का फैसला टाल रहे हैं। पुरी ने कहा कि अब आवासीय मांग में वृद्धि मुख्य रूप से प्रीमियम आवास, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) आधारित रोजगार केंद्रों और बुनियादी ढांचा विकास वाले क्षेत्रों तक सीमित होती जा रही है। एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार, इन सात शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान नई आवासीय परियोजनाओं की पेशकश व आपूर्ति सात प्रतिशत बढ़कर 1,06,000 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 98,625 इकाई थी। सलाहकार कंपनी ने कहा कि इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में इन सातों शहरों में औसत आवासीय कीमत में सालाना आधार पर सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर में आवासीय कीमतों में सबसे अधिक 13 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।

गलती सुधारो, कार्रवाई से बचो- जन विश्वास कानून के तहत कारोबारियों और एमएसएमई को सरकार की बड़ी राहत

नई दिल्ली । देश के कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक राहत भरी खबर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस (सुधार नोटिस) का नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। इस नए नियम का सीधा सा मतलब है- पहले गलती सुधारो, कार्रवाई का सामना बाद में करो। यह बदलाव जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के जरिए लागू किया गया है, ताकि पहली बार अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए व्यवसायों को सीधे जुर्माने या कानूनी पचड़े में न पड़ना पड़े। अब तक नियमों के मामूली उल्लंघन पर भी सीधी दंडात्मक कार्रवाई होती थी। लेकिन नए तंत्र के तहत,

यदि कोई लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी पहली बार किसी प्रक्रियात्मक या नियामक खामी को पकड़ता है, तो वह सीधे कार्रवाई करने के बजाय एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि गलती क्या है और इसे सुधारने के लिए कारोबारी को एक उचित समय दिया जाएगा। यदि संबंधित इकाई तय समय के भीतर नियमों का पालन कर लेती है, तो वह दंडात्मक कार्यवाही से पूरी तरह बच सकती है। पहली बार की जाने वाली जिन गलतियों पर यह नोटिस मिलेगा, उनमें पंजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, मॉडल अप्रूवल, वजन और माप उपकरणों के निर्माण व बिक्री, पैकेटबंद वस्तुओं के लेनदेन और वैधानिक जानकारी देने में हुई चूक शामिल है। यह एक लाजमी सवाल है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नए सिस्टम से उपभोक्ता संरक्षण किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा और न ही प्रवर्तन में कोई ढील दी जाएगी।

विभाग के बयान के अनुसार, ÷यदि कोई इम्प्रूवमेंट नोटिस का पालन नहीं करता है या बार-बार नियमों की अनदेखी करता है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी÷। इसके अलावा, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कृत्यों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी यह सुधार ईमानदार कारोबारियों को नियमों के पालन में मदद करने और लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम की प्रामाणिकता बनाए रखने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है।

अब प्रवर्तन एजेंसियां अपना पूरा ध्यान और संसाधन उन जानबूझकर किए गए और बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर केंद्रित कर सकेंगी, जो वास्तव में उपभोक्ताओं के हितों पर असर डालते हैं। यह कदम भारतीय कारोबारी माहौल को और अधिक पारदर्शी और भयमुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।